



AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रं .155/2008

28/08/2019 को निर्णय सुरक्षित

06/09/2019 को निर्णय घोषित किया गया

भावेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान दास चंद्राकर

उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम डंगनिया

पटवारी हल्का क्रमांक 112 पी/ओ डंगनिया,

तहसील गुंडरदेही, जिला. दुर्ग, छत्तीसगढ़.

--- अपीलकर्ता/वादी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला दुर्ग,

---- प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

अपीलकर्ता के लिए: श्री विपिन तिवारी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/राज्य के लिए : श्री अंशुमन राबरा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
सी.ए.वी. निर्णय

1. वादी द्वारा सी.पी.सी. की धारा 100 के अंतर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील में विधि के सारवान प्रश्न की स्वीकृति एवं निर्माण के प्रश्न पर सुनवाई की गई।



2. अपीलकर्ता/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विपिन तिवारी ने प्रस्तुत किया कि निचली दोनों अदालतों ने वादी द्वारा दायर सिविल मुकदमे को यह मानकर खारिज कर दिया कि वादी ने मुकदमे की भूमि पर अतिक्रमण किया है, ऐसा निष्कर्ष दर्ज किया जो बिल्कुल अनुचित है, रिकॉर्ड के विपरीत है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह 1947-48 से मुकदमे की भूमि पर स्थापित कब्जे में है, उसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से वाद भूमि पर अपना अधिकार पूर्ण कर लिया है और इसलिए, दूसरी अपील में निर्धारण हेतु विधि का सारवान प्रश्न शामिल है और इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।

3. अपीलकर्ता/वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए दायर मुकदमे में कहा गया है कि वह 1947-48 से मुकदमे की भूमि पर स्थापित कब्जे में है, और यह कब्जा प्रतिकूल कब्जे में परिणत हो गया है और वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मुकदमे की भूमि पर घोषणा की डिक्री के लिए हकदार है। प्रतिवादी/राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अपना लिखित बयान दर्ज किया कि पुराना खसरा नंबर 104 क्षेत्र 0.845 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में घास की भूमि के रूप में दर्ज है और इसे कभी भी भूमिस्वामी भूमि के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, और इसलिए, वादी सरकारी घास की भूमि पर अतिक्रमणकारी है और छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57(2) के तहत उसके आवेदन को विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही रूप से खारिज कर दिया गया था, इस तरह, स्वामित्व की



घोषणा के लिए वादी का मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करते हुए वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमे की जमीन सरकारी घास की जमीन है और वादी मुकदमे की जमीन के कुछ हिस्से पर काबिज है और 1974 से उक्त मुकदमे की जमीन पर अतिक्रमणकारी है, और आगे यह भी माना कि मुकदमा परिसीमा अवधि के अनुसार वर्जित है। वादी द्वारा सीपीसी की धारा 96 के तहत दायर की गई अपील में, विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील को खारिज करके ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री की पुष्टि की।

5. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वादी, जो 1974 से अतिक्रमणकारी के रूप में वाद भूमि के एक हिस्से पर काबिज है, ने तब से काबिज रहकर वाद भूमि पर अपना पूर्ण स्वामित्व स्थापित कर लिया है।

6. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 112 में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वाद दायर करने के लिए परिसीमा अवधि का प्रावधान है: -

112	केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के, जिसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार आती है, द्वारा या	तीस वर्ष	जब किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा लाए गए वैसे ही वाद में परिसीमा काल इस अधिनियम के
-----	---	----------	--



	उसकी ओर से कोई भी वाद (सिवाय ऐसे वाद के जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसकी आरंभिक अधिकारिता प्रयोग में हो)।		अधीन चलना आरंभ हो जाता।
--	---	--	-------------------------

7. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार के विरुद्ध परिसीमा अवधि 30 वर्ष है, कोई व्यक्ति केवल 30 वर्षों तक कब्जे को साबित करके ही अपने कब्जे को सरकार के विरुद्ध पूर्ण स्वामित्व में बदल सकता है। सरकार के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए, किसी व्यक्ति को पूर्ण वैधानिक अवधि के लिए ऐसा कब्जा साबित करना होगा और उसे प्रतिकूल कब्जे को साबित करना होगा। इसलिए, केवल लंबे समय तक कब्जे के सबूत के आधार पर, राज्य पर यह दिखाने का भार नहीं आता है कि उसने अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई अवधि के भीतर कब्जा रखा था।

8. सीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 112 पुराने परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 144 का पैरा मैटेरिया प्रावधान है। प्रांतीय सरकार, मध्य प्रांत और बरार बनाम गोविंदराव तुकाराम¹ के मामले में, सीमा अधिनियम, 1908 के पुराने अनुच्छेद 144 के तहत प्रतिकूल कब्जे पर विचार करते हुए, नागपुर उच्च न्यायालय ने माना है कि सभी भूमि पर मौलिक अधिकार रखने वाली सरकार के खिलाफ कब्जे का अधिकार नहीं हो सकता है और एक



व्यक्ति को लगातार 60 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे को साबित करना होगा और निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"यह कि एक कब्जाकारी स्वामित्व सभी के विरुद्ध अच्छा है, लेकिन सच्चे स्वामी के विरुद्ध, एक प्रस्ताव है जिसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सरकार के पास सभी भूमि पर मौलिक अधिकार है और इसलिए, वह असली स्वामी है। तदनुसार एक व्यक्ति जो कब्जे के आधार पर स्वामित्व पर निर्भर करता है, वह सरकार के विरुद्ध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह यह न दिखा दे कि सरकार ने किसी तरह से अपने स्वामित्व को वादी या उसके पूर्ववर्तियों को दे दिया है या वादी और उसके पूर्ववर्तियों ने सरकार के विरुद्ध प्रतिकूल रूप से कब्जा कर रखा है और इसलिए उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के द्वारा सरकार के विरुद्ध एक अच्छा स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। सरकार के मामले में 60 वर्ष का प्रतिकूल कब्जा होना आवश्यक है।"

आगे यह माना गया कि लंबी अवधि तक लगातार और निर्बाध कब्जे से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वामित्व के साथ कब्जा है, लेकिन यह राज्य सरकार के मामले में लागू नहीं होगा: -

"लंबी अवधि तक लगातार और निर्बाध कब्जे से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के पास कब्जा है, वह वैधानिक अवधि से कम समय होने पर भी मालिकाना हक रखता है। यह अनुमान निजी व्यक्तियों के बीच के मामले में लागू हो सकता है, लेकिन यह उस निकाय के मामले में लागू नहीं हो सकता है जिसके पास मौलिक अधिकार निहित है, जैसे कि सरकार।"

9. जो व्यक्ति अपने स्वामित्व को प्रतिकूल कब्जे पर आधारित करता है, उसे स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा यह दिखाना होगा कि उसका कब्जा वास्तविक स्वामी के प्रति शत्रुतापूर्ण था और दावा की गई संपत्ति पर उसके



स्वामित्व से वंचित करने के बराबर था। यह तय करने में कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा आरोपित किए गए कार्य प्रतिकूल कब्जे का गठन करते हैं, उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति की शत्रुता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता लगाया जाना चाहिए। इसलिए, जो व्यक्ति अपने स्वामित्व को प्रतिकूल कब्जे पर आधारित करता है, उसे स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा यह दिखाना होगा कि उसका कब्जा वास्तविक स्वामी के प्रति शत्रुतापूर्ण था और दावा की गई संपत्ति पर उसके स्वामित्व से वंचित करने के बराबर था। [कृपया देखें अन्नासाहेब बापूसाहेब पाटिल और अन्य बनाम बलवंत @ बालासाहेब बाबूसाहेब पाटिल (मृत) एलआर द्वारा एवं वारिसान और अन्य²]

10. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिकूल कब्जे के द्वारा स्वामित्व सरकार के विरुद्ध भी निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन जहां सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के दावे का संबंध है, इस प्रश्न पर अधिक गंभीरता और प्रभावी ढंग से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें अंततः अचल संपत्ति पर राज्य के अधिकार और स्वामित्व का विनाश और तीसरे पक्ष के अतिक्रमणकर्ता को स्वामित्व प्रदान करना शामिल है, जबकि उसके पास कोई स्वामित्व नहीं था। [देखें राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह (मृत) अपने विधिक प्रतिनिधी के द्वारा³]

11. उच्चतम न्यायालय ने आर. हनुमय्या एवं अन्य बनाम कर्नाटक सरकार के सचिव, राजस्व विभाग एवं अन्य⁴ के मामले में माना है कि प्रतिकूल कब्जे

² (1995) 2 एस सी सी 543

³ (2000) 5 एस सी सी 652

⁴ (2010) 5 एस सी सी 203



की दलील को स्थापित करने के लिए सीमा अवधि तीस वर्ष होगी और इसके अतिरिक्त उसने सरकार के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे में आवश्यक सबूत की प्रकृति को इंगित करते हुए कानून के सिद्धांत भी निर्धारित किए हैं, जिन्हें नीचे पुनः उद्धृत किया गया है: -

सरकार के विरुद्ध स्वामित्व की घोषणा के लिए वादों में आवश्यक प्रमाण की प्रकृति

"19. सरकार के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमे, हालांकि निजी व्यक्तियों के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा के मुकदमों के समान हैं, लेकिन कुछ पहलुओं में काफी भिन्न हैं। पहला अंतर सरकार के पक्ष में उपलब्ध उपधारणा के संबंध में है। सभी भूमि जो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है या जो किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित नहीं है, सरकार की है। सभी खाली भूमि सरकार की संपत्ति है, जब तक कि कोई व्यक्ति ऐसी किसी भूमि पर अपना अधिकार या स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकता। सरकार के लिए उपलब्ध यह उपधारणा किसी व्यक्ति या व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा अंतर उस अवधि के संबंध में है जिसके लिए स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वामित्व और/या कब्जा स्थापित किया जाना है। बारह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्वामित्व/कब्जा स्थापित करना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ घोषणात्मक मुकदमे में स्वामित्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार के खिलाफ स्वामित्व के लिए घोषणात्मक मुकदमे में सफल होने के लिए तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्वामित्व/कब्जा स्थापित करना होगा। यह परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 112 का अनुसरण करता है, जो निजी व्यक्तियों द्वारा मुकदमों के लिए 12 वर्ष की अवधि के मुकाबले सरकार द्वारा मुकदमों के संबंध में तीस वर्ष की लंबी अवधि निर्धारित करता है। कारण स्पष्ट है। सरकारी संपत्तियां पूरे राज्य में फैली हुई हैं और सरकार के लिए



अपनी संपत्तियों को अतिक्रमणों से बचाना या सुरक्षित रखना हमेशा संभव नहीं होता है। कई बार, इसके अपने अधिकारी, जिनसे इसकी संपत्तियों की रक्षा करने और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, या तो लापरवाही या मिलीभगत के कारण, निजी पक्षों को सरकार के खिलाफ स्वामित्व या कब्जे का दावा करने में मदद करने के लिए रिकॉर्ड में प्रविष्टियां बना देते हैं। सरकारी संपत्ति का कोई भी नुकसान अंततः समुदाय का नुकसान है। अदालतों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहें कि सार्वजनिक संपत्ति को बेईमान तत्वों द्वारा निजी संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया जाए।

20. कई सिविल न्यायालय सरकार के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा के मुकदमों को, सरकारी संपत्तियों से संबंधित विशेष विशेषताओं की अनदेखी या अनदेखी करते हुए, लापरवाही से निपटाते हैं। सरकार के खिलाफ ऐसे मुकदमों के उदाहरण आम हैं, जो या तो एकतरफा या उचित प्रतिवाद के अभाव में, केवल वादी के मौखिक दावों या भटकी हुई राजस्व प्रविष्टियों पर कार्रवाई करते हुए, नियमित रूप से तय किए जाते हैं। चाहे सरकार मुकदमों का विरोध करे या न करे, सरकार के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा तय होने से पहले, वादी को या तो स्वामित्व विलेख प्रस्तुत करके अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहिए जो मुकदमे की तारीख से पहले कम से कम तीस साल की अवधि के लिए स्वामित्व का संतोषजनक रूप से पता लगाता है (सिवाय इसके कि जहां स्वामित्व सरकार या किसी वैधानिक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुदान या हस्तांतरण के संदर्भ में दावा किया जाता है), या तीस साल से अधिक की अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके। ऐसे मुकदमों में, न्यायालय सरकार के पक्ष में उपलब्ध पूर्वधारणाओं की अनदेखी करते हुए, सरकार के विरुद्ध घोषणात्मक या निषेधात्मक आदेश नहीं दे सकते हैं, इस आधार पर कि वाद में निहित ऐसे कथन, जिनका खंडन या उल्लंघन नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार या स्वीकृत मान लिया गया है।

21. न्यायालय को सरकार के विरुद्ध स्वामित्व घोषित करने का आदेश देने से पहले निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर अवश्य



प्राप्त करना चाहिए: क्या वादी ने तीस वर्ष से अधिक की अवधि के स्वामित्व का पता लगाने वाले स्वामित्व विलेख प्रस्तुत किए हैं; या क्या वादी ने सरकार के ज्ञान में तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपना प्रतिकूल कब्जा स्थापित किया है, ताकि उसके कब्जे को स्वामित्व में परिवर्तित किया जा सके। उस प्रश्न के साथ-साथ न्यायालय को यह भी पता लगाना चाहिए कि क्या वादी को राजस्व अभिलेखों या नगरपालिका अभिलेखों में तीस वर्ष से अधिक समय से संपत्ति का स्वामी, धारक या अधिभोगी के रूप में दर्ज किया गया है, और यदि वादी के पास कब्जा है, तो उसके द्वारा दावा किए गए कब्जे की प्रकृति क्या है - अधिकृत या अनधिकृत; अनुमोदक; आकस्मिक और सामयिक; गुप्त और अवैध; खुला, निरंतर और प्रतिकूल; माना गया या निहित (स्वामित्व के बाद)।

22. स्वामित्व का दावा करने की भावना के बिना केवल अस्थायी उपयोग या कब्जा या केवल सहनशीलता के साथ उपयोग करना सरकार के प्रतिकूल कोई अधिकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकार के स्वामित्व को हटाने या उसे विफल करने के लिए, दावेदार को एक स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना होगा जो सरकार के स्वामित्व से बेहतर या उससे बेहतर हो या सरकार के ज्ञान के साथ तीस साल से अधिक की अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व की पूर्णता स्थापित करें। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए, दावेदार का कब्जा वास्तविक, खुला और दृश्यमान होना चाहिए, मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण (और इसलिए आवश्यक रूप से मालिक के ज्ञान के साथ) और सीमा के कानून के तहत एक अवरोध बनाने के लिए आवश्यक पूरी अवधि के दौरान जारी रहना चाहिए। संक्षेप में, यह निरंतरता, प्रचार और विस्तार में पर्याप्त होना चाहिए। केवल अस्पष्ट या संदिग्ध दावे कि दावेदार प्रतिकूल कब्जे में रहा है, पर्याप्त नहीं होंगे। एक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए अस्पष्ट रूप से भटकाव या छिटपुट प्रविष्टियाँ पर्याप्त नहीं होंगी और उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।

23. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई बार किसी निजी नागरिक के लिए सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से



सरकारी भूमि पर अपना नाम दर्ज करवाना संभव होता है। केवल अनुदान, स्वामित्व विलेख आदि जैसे उचित दस्तावेजों पर आधारित प्रविष्टियाँ या ऐसे कब्जे को मान्यता देने और उचित प्रविष्टियाँ करने के लिए अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे के वास्तविक सत्यापन के आधार पर सरकार के खिलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने स्वभाव से, प्रतिकूल कब्जे पर आधारित दावे के लिए स्पष्ट और स्पष्ट दलीलों और सबूतों की आवश्यकता होती है, और भी अधिक, अगर यह सरकार के खिलाफ़ है। चाहे जो भी हो।”

12. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 सभी भूमि पर राज्य के स्वामित्व का प्रावधान करती है, जो इस प्रकार है:-

“धारा 57. समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व:- (1)
समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं और एकद्वारा यह घोषित किया जाता है कि समस्त ऐसी भूमियाँ जिनके अन्तर्गत रुका हुआ पानी, खानें खदानें, खनिज तथा वन चाहे वे आरक्षित हों या न हों, तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार हैं, राज्य सरकार संपत्ति है:

परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति के किसी ऐसी सम्पत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर जो कि इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहें हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझा जाएगी ।

(2) जहां राज्य तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां विवाद ²[कलेक्टर] द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(3)XX.....

(4)XX.....”

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों के प्रकाश में, और संहिता की



धारा 57 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो सभी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को प्रदान करता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी द्वारा दायर राजस्व अभिलेखों में मुकदमे की भूमि घास की भूमि के रूप में दर्ज है (प्रदर्श पी/5 और पी/6) और केवल उक्त दस्तावेजों के टिप्पणी कॉलम (12) में वादी के पिता का नाम दर्ज है। प्रदर्श पी/7 में भी मुकदमे की भूमि को घास की भूमि के रूप में दर्ज किया गया है और कॉलम संख्या 16 में उल्लेख किया गया है कि वादी के पिता को मुकदमे की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा दिखाया गया है और इसके अलावा, वादी द्वारा अपना कब्जा साबित करने के लिए कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।

वादी को इस प्रकार दायर राजस्व अभिलेखों में मुकदमे की भूमि के मालिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है और मुकदमे की भूमि पर उसका स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। सरकार के बचाव की कमजोरी या प्रतिवाद की अनुपस्थिति सरकार के खिलाफ घोषणात्मक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करने में विफल रहा है। नीचे की दोनों अदालतों ने सही निष्कर्ष निकाला है कि मुकदमे की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली घास की भूमि है और वादी 1974 से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, वह भी मुकदमे की भूमि के कुछ हिस्से में, जैसा कि निर्धारित तीस साल की अवधि 2004 को पूरी होगी, इस प्रकार, वह यह प्रदर्शित करने में भी विफल रहा है कि वह 30 वर्षों की वैधानिक अवधि के लिए मुकदमे की भूमि पर स्थापित और निर्विवाद कब्जे में है। इस



संबंध में नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य रिकॉर्ड पर आधारित तथ्य हैं, जो न तो विकृत हैं और न ही रिकॉर्ड के विपरीत हैं। मुझे इस दूसरी अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं लगता।

14. तदनुसार दूसरे पक्ष को नोटिस दिये बिना लिमिने दूसरी अपील खारिज की जाये । कोई व्यय नहीं ।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

